

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

जगदीश

बनाम

रमेश वगै०

प्रार्थना पत्र संख्या : 199 / 2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02-08-2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हित में खातेदार गोपी पुत्र नोन्दा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र हस्तांतरित स्वअर्जित सम्पत्ति है, जो कि नियमानुसार गोपी पुत्र नोन्दा के हित में खातेदारी इन्द्राज होने के उपरान्त नियमानुसार के कब्जे काश्त व मालिकाना स्वामित्व के तहत खातेदारी अंकित की गई है, जो कि बदस्तुर रहते हुए खातेदार रहा है जिसके अनुशरण में खातेदार की हैसियत से जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हित में दिनांक 17.02.1988 को निष्पादित व पंजिबद्ध किया गया, जिनकी खातेदारी अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है, जिसको माननीय न्यायालय में चूनीती नहीं दिया जा सकता है। जिसके संबंध में वादी ने मुश्तर्का पैतृक हक खातेदारी अनुसार हक घोषणा हेतु वाद पेश किया है, जबकि विवादित भूमि पैतृक वंशानुगत खातेदारी नहीं होकर मात्र मिन प्रतिवादी की स्वअर्जित भूमि है, जिसके विरुद्ध वादी किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है, जो कि प्रस्तुत वाद कतई ही चलने योग्य नहीं है, मात्र खारिज करने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में तथाकथित व फर्जी बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जो कि प्रतिवादी के हितों के विरुद्ध वादी की सुनियोजित षडयंत्रपूर्ण कूटरचित दस्तावेज है, जिसके आधार पर माननीय राजस्व न्यायालय से विचाराधीन वाद में वादी हक घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है तथा नियमानुसार खातेदारी अंकित होकर मिन प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हित में निष्पादित व पंजिबद्ध विक्रय पत्र में अंकित विवादित भूमि अनुसार खातेदारी मिन प्रतिवादी के राजस्व इन्द्राज खातेदारी के विरुद्ध राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत वाद पर सुनवाई करने एवं निर्णय करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को कतई ही नहीं है। जिसके तहत भी विचाराधीन वाद गार्ड वाई लॉ होने के कारण इसी प्रकम पर खारिज करने योग्य है। वाद में अंकित विवादित भूमि मिन प्रतिवादी के हित में निष्पादित पंजिबद्ध विक्रय अनुसार खातेदारी अंकित है तथा मिन प्रतिवादी के स्वअर्जित अधिकारों के विरुद्ध तथाकथित वादी की संदेहास्पद व अविश्वसनीय दस्तावेज है, जिसके आधार पर माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा मिन प्रतिवादी के विरुद्ध वादी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मिन प्रतिवादी के हित में पंजिबद्ध विक्रय पत्र के विक्रय पत्र के विरुद्ध हक घोषणा के कथनों अनुसार मिन प्रतिवादी के विरुद्ध हक घोषणा कराने एवं करने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय में कतई ही नहीं आता है। जो कि प्रस्तुत वाद विधि विरुद्ध होकर खारिज करने योग्य है। विवादित भूमि को बहसियत रिकार्डेड खातेदार गोपी पुत्र नोन्दा ने अपनी भूमि का विक्रय मिन प्रतिवादी के हित में आज से 30 वर्ष निष्पादित व पंजिबद्ध कराया, जिसके आधार पर खातेदारी अंकित होकर प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हित में करते हुए मौके पर कब्जा हस्तान्तरण कर दिया है। जिसके</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

अनुसार विक्रय पत्र भी प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हित में निष्पादित करते हुए उप पंजीयक जगवारामगढ़ के कार्यालय में पंजिबद्ध करा दिया गया और खातेदारी भूमि मिन प्रतिवादी के हित में अंकित किया गया तथा भूमि वादग्रस्त पर मिन प्रतिवादी भूमि के खातेदार काश्तकार चला आया है, जिसके अनुसार विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार व मालिक प्रतिवादी 1 व 2 चले आ रहे हैं। जिसके अनुसार वादी द्वारा तथाकथित फर्जी व बनावटी कूटरचित दस्तावेज मिन प्रतिवादी के विधिक अधिकारों के विरुद्ध कतई ही निष्प्रभावी हैं तथा विवादित भूमि के संबंध में खातेदार गोपी पुत्र नोन्दा की प्रक्रिया को निरस्त कराने व उसके बाद मिन प्रतिवादी के हित में निष्पादित व पंजिबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना व निष्प्रभावी घोषित कराने बिना या पंजिकृत दस्तावेज को निष्प्रभावी घोषित करने या उसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद कतई ही खारिज करने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में निष्पादित विक्रय पत्र को वादी ने सक्षम सिविल न्यायालय में चूनीती नहीं दिया है तथा अब विचाराधीन वाद में मिन प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हित में पंजिबद्ध विक्रय पत्र को अब निरस्त करने व प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा विक्रय पत्र प्रभाव शून्य घोषित होने से पूर्व वादी के हित में विचाराधीन वाद में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, ऐसी स्थिति में वाद मात्र खारिज करने योग्य है। वादी का वाद विधि विरुद्ध होने से व वाद मात्र बोगस लिटिगेशन अनुसार विचाराधीन है जो मात्र इसी प्रकम पर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी / वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आ० 7 नि० 11 सी० पी० सी० में अंकित बिन्दुओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि प्रा० पत्र का मद सं० 1 पूर्णतः कपोल कल्पित एवं मनगन्धत होने से अस्वीकार है। वादी की खातेदारी को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र कय करने का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी सं० 1 व 2 को नहीं था। प्रार्थी के पक्ष में कराया गा विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही अप्रार्थी/वादी के हक अधिकारों के विरुद्ध शून्य है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी/वादी के हिस्से पर प्रार्थी किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है ना ही कभी रहा है। वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी का है जिसे सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। वादी / अप्रार्थी का वाद घोषणा खातेदारी को है जो किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र जवाब दावे से बचने एवं वाद को लम्बे समय तक लम्बित रखने की गरज से माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मन्त्र करने व पत्रावली में उपलब्ध वादी के वाद पत्र, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., जवाब प्रा० पत्र आ० 7(11) एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी / प्रतिवादी सं० 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० को स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी / प्रतिवादी सं० 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० को स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज० काश्तकारी अधि० को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपस्थित अधिकारी
जगवारामगढ़ जिला-प्रमुख